

the importance and need to evolve a national food policy;

(b) if so, the major observations and suggestions made at the Conference towards the evolving of national food policy and what were the broad aspects of the national food policy as projected and evolved at the said conference; and

(c) Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) to (c). A Conference of Delhi Malayalee Association was held in the middle of April, 1968, to discuss national food policy with special reference to Kerala. The report giving the consensus of the conference has been received a couple of days back and will be examined.

मध्य प्रदेश में खेती का जोरदार कार्यक्रम

*1761. श्री ग० च० दीक्षित : क्या खाद्य तथा कृषि यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में वर्ष 1968 के सघन खेती का जोरदार कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या यह सच है कि कार्यक्रम विचार अनुमोदन तथा अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार को पेश किया गया था;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय सहायता मंजूर की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कितना लाभ हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्डे) : (क) और (ख). अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम आदि की सामान्य प्लान स्कीमों के अतिरिक्त, जो समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं और उनपर विचार होता रहता है, मध्य प्रदेश सरकार से सघन खेती के लिये कौशल कार्यक्रम के रूप में कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं होते ।

Disconnection of Telephone Lines of M.Ps.

*1762. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that telephone lines of many Members of Lok Sabha and Rajya Sabha at their permanent residences were disconnected for non-payment of telephone bills, when they came to Delhi for attending Parliament Sessions ;

(b) if so, the number of such cases since April, 1967 ; and

(c) whether Government propose to review the policy of payment of telephone bills by the Members of Parliament to avoid inconveniences faced by them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) and (b). The telephones of Members of Parliament are not immune from disconnection for non-payment of telephone dues. The number of cases in which their telephones were disconnected for non-payment is not readily available as data regarding disconnection of telephones is kept according to telephone numbers.

(c) No, Sir.

खेतिहर श्रमिकों सम्बन्धी अध्ययन दल

*1762-क. श्री देवराव पाटिल : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के खेतिहर श्रमिकों की स्थिति और उनके विकास के बारे में अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा क्या सिफारिशों की गई हैं, और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।